हिन्दुस्तान 20

स्कूलों से हटें 'सरकारी' टैग तो सुधरेगी सूरत

जवाब-तलब

मैग्सेसे अवार्ड विजेता समाजसेवी संदीप पाण्डेय छह दिन तक अनशन पर बैठे। आम जनता के सामने एक सवाल उठाया... सरकारी स्कूलों में अधिकारियों के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? इस सवाल ने सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। इन सरकारी स्कूलों पर हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। नेताओं से लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारी तक इनकी स्थिति में सुधार के रोज नए दावे कर रहे हैं। लेकिन कोई भी अधिकारी खुद अपने बच्चों को इन स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहता। 'हिन्दुस्तान' ने शिक्षा विभाग के अफसरों के सामने तीन सवाल उठाए। अधिकारियों के जवाब पर एक रिपोर्ट:

हिन्दुस्तान के तीन सवाल

सवाल -1 : आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं?
सवाल -2 : आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते?
सवाल -3 : कैसे इस कमी को दूर किया जाए?

अधिकारियों के जवाब

01 उमेश त्रिपाठी, जिला विद्यालय निरीक्षक

राजकीय स्कूलों की ब्रांडिंग नहीं

जवाब-1: मैं खुद गोरखपुर के एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं। बेटी सरस्वती शिशु मंदिर में है। दो बेटे मिलेनियम स्कूल में पढ़ते हैं।
जवाब-2: लोगों की सोच है कि प्राइवेट स्कूल अच्छे होते हैं। इसीलिए प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराया।
जवाब-3: लखनऊ के कई राजकीय स्कूल काफी बेहतर हैं। कमी सिर्फ ब्रांडिंग की है।

02 प्रवीण मणि त्रिपाठी, बेसिक शिक्षा अधिकारी

शिक्षकों को पढ़ाने का समय दें

जवाब-1: बच्चे प्राइवेट स्कूल में हैं।
जवाब - 2: प्राइवेट स्कूल के बच्चे कॉम्पटीशन में आगे हैं।
जवाब-3: सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को दूसरे कामों में कम इस्तेमाल किया जाए। साल में 200 दिन तो पढ़ाने का मौका मिले।

03 केके गुप्ता, संयुक्त शिक्षा निदेशक

सरकारी स्कूल अनुशासनहीन

जवाब-1: दो बच्चे सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में हैं।
जवाब-2: अनुशासनहीनता के कारण बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजा।
जवाब-3: शिक्षकों में कोई कमी नहीं है। उनकी पदोन्नति को बच्चों के प्रदर्शन से जोड़ें तो पढ़ाई होगी।

इन जिम्मेदारों ने तो साध ली चुप्पी

गरीब बच्चों के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा का मुद्दा बेहद गंभीर है। शिक्षा विभाग के जिन अधिकारियों को इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का जिम्मा दिया गया है वह इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अमर नाथ वर्मा, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा निदेशक दिनेश बाबू शर्मा से मोबाइल नम्बर सम्पर्क किया। एसएमएस भेजा लेकिन जवाब नहीं मिला।

जुबली में दाखिले के लिए लाइन लगती थी ...

आज लोग भले ही सरकारी स्कूलों से दूरी बना रहे हो लेकिन एक जमाने में राजकीय जुबली इंटर कॉलेज और दूसरे सरकारी स्कूल शहर की शान थे। जुबली इंटर कॉलेज 1889 में शुरू हुआ। इतिहासकार योगेश प्रवीण बताते हैं कि उस जमाने में ला माट्र्स, लौरेटो जैसे स्कूलों में ज्यादातर अंग्रेजों के बच्चे पढ़ते थे। प्रतिष्ठित भारतीय परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई।

यहां से निकले कई नगीने

डीजीपी होमगार्ड अतुल, एडीजी विजलेंस भानू प्रताप, महापौर डॉ. दिनेश शर्मा, न्यायाधीश हैदर अब्बास रजा, न्यायाधीश स्वर्गीय वीरेन्द्र भाटिया, सीए राजीव अग्रवाल, सीए नीरज चौहान जैसी कई हस्तियों ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की।

...तो सुधर जाएगी सरकारी स्कूलों की तस्वीर

सरकारी अधिकारी शिक्षा पर खूब बजट खर्च करते हैं। क्यों नहीं अपने बच्चों को यहां भेजते। जिस दिन अधिकारियों के बच्चे पढ़ने लगेंगे, इनकी तस्वीर बदल जाएगी- संदीप पाण्डेय, समाजसेवी

शिक्षा विभाग के अधिकारी मंथन करें। जब वह ही अपने स्कूलों पर भरोसा नहीं करेंगे तो आम जनता क्यों करेगी? तस्वीर सुधारने के लिए ईमानदार कोशिश जरूरी है — गोपाल भारती, समाजसेवी

जिनके पास इन स्कूलों को बेहतर करने की जिम्मेदारी है। उनका कोई भावनात्मक लगाव ही नहीं है। सिर्फ नौकरी की तरह करते हैं। अगर यह ये करें तो तस्वीर सुधर जाएगी—समीना बानो, समाजसेवी

केन्द्रीय विद्यालय तो रोल मॉडल हैं

केन्द्रीय विद्यालय इस मामले में रोल मॉडल हैं। यहां सिपाही से लेकर कर्नल और मेजर के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। संदीप पाण्डेय कहते हैं कि केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूलों के पैटर्न को अपनाया जा सकता है।